

## प्रकाशनार्थ

पटना, 12 मार्च। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (आइजीसी), एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आट्री) और बिहार सरकार के महिला विकास निगम द्वारा आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का शीर्षक “अर्थव्यवस्था में महिलाएं - समकालीन मुद्दे और भावी रास्ते” था। पैनल का संचालन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की प्रिया नंदा द्वारा किया गया। पैनल में आट्री की अस्मिता गुप्ता, अशोका विश्वविद्यालय की अश्विनी देशपांडे, बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति (जीविका) के बालामुरुगन डी., अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शेर सिंह वेरिक, विश्व बैंक की शुभा चक्रबर्ती और इनिशिएटिव फॉर हवाट वर्क्स टू एडवांस वीमन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी (ईवेज) की सौम्या कपूर मेहता शामिल थीं।

अस्मिता गुप्ता ने कहा कि महिलाओं का काम सिर्फ लैंगिक मुद्दा नहीं, व्यापक आर्थिक मुद्दा भी है। अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन दर्शाता है कि मौजूदा कानूनी ढांचों और अन्य प्रोत्साहनों के चलते प्रतियोगिता के कारण कंपनियों में महिला श्रमिकों की कम मांग रहती है। व्यापार के उदारीकरण पर उनका काम इसका स्पष्ट उदाहरण है। इन कानूनी ढांचों का मकसद महिलाओं को लाभ पहुंचाना रहा है लेकिन इनसे महिलाओं की भागीदारी को नुकसान पहुंच रहा है। और महिला श्रमिक के संबंध में चिंता सिर्फ आपूर्तिपक्षीय नहीं है। यह मांग और आपूर्ति, दोनों पक्षों का मामला है।

अश्विनी देशपांडे ने कहा कि श्रमशक्ति में महिलाओं की माप संबंधी मामला कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है। खास कर महिलाओं द्वारा परिवार का काम आर्थिक कार्य है जिसको काम में नहीं गिना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले ‘देखरेख कार्य’ का विस्तार करके ‘पुनरुत्पादक श्रम’ में शामिल करने की जरूरत है जिसमें रोज दिन में कई बार किए जाने वाले दैनिक घरेलू काम शामिल हैं।

वहीं, बालामुरुगन डी. ने कहा कि जीविका में हुआ उनका अनुभव बहुत सक्षम महिलाओं की गाथा सामने लाता है जिन्होंने अभी मौजूद मान्यता को कि कुछ काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं, चुनौती देते हुए 20 लाख सोलर लैंप एसेंबल किए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जीविका में ‘कन्युनिटी मोबिलाइजर’ की भूमिका में महिलाएं वर्चस्व की स्थिति में हैं जो पहले सिर्फ पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता था। इसलिए यह इस प्रचलित मान्यता को चुनौती देता है कि महिलाओं के लिए कुछ तरह के काम ही उपयुक्त हैं।

शेर सिंह वेरिक का कहना था कि जिन देशों में ढांचागत परिवर्तन हुआ है, उनमें भी महिलाओं की भागीदारी कम है और जेंडर संबंधी मुद्दे बरकरार हैं। इसलिए विकास का पैटर्न और विकास की प्रकृति के साथ-साथ सामाजिक प्रचलन भी मुख्य बाधा हैं।

शुभा चक्रबर्ती ने अपनी चिंता प्रकट की कि महिलाओं की पसंद को अनेक सामाजिक प्रचलनों के जरिए बाधित किया जाता है। विवाह की उम्मीद भी उनमें से एक है जो महिलाओं के लिए श्रमशक्ति में प्रवेश और काम में लंबे समय तक बने रहने को सीमित कर देता है।

सौम्या कपूर मेहता का कहना था कि व्यापक अर्थव्यवस्था का मांग पक्ष महिलाओं के लिए काम करने की गुंजाइश और लचीलापन देता है। लेकिन व्यापक अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए मातृत्व लाभों और पलनाघर की सुविधाओं के बारे में भी सोचना जरूरी है।

आट्री के सदस्य सचिव प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने समापन वक्तव्य देते हुए महिलाओं के योगदान को सामने लाने के लिए माप संबंधी मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने महिलाओं के ‘समय-उपयोग सर्वेक्षण’ का उल्लेख किया जिसमें महिलाओं द्वारा पूरे दिन में किए गए काम के समय को मापा जाता है जिससे महिलाओं के योगदान की बेहतर तस्वीर उभरती है।

(अंजनी कुमार वर्मा)